मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर, व न्यायधीश सूर्य कांत, के समक्ष

बलदेव सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2006 का 12838

10 दिसंबर, 2008

भारत का संविधान, 1950– अनुच्छेद 226– हरियाणा ईंट आपूर्ति नियंत्रण आदेश, 1972– खंड 21–पूर्वी पंजाब ईंटों का नियंत्रण आपूर्ति अधिनियम, 1949– धारा 3– जनहित याचिका– ईंट भट्ठा– की स्थापना– गांव की आबादी और स्कूल से निर्धारित दूरी– निदेशक, खाद्य आपूर्ति गांव की आबादी से ईंट भट्ठे की दूरी की शर्त के संबंध में कुछ शर्तें लगाके छूट देते हुए स्कूल- ईंट भट्ठा एसपीएम स्तर को 750 की निर्धारित सीमा के 1/5वें या 1/6वें हिस्से तक कम करने में विफल रहा - ईंट भट्ठा लाइसेंस में निहित शर्तों का सम्मान और अनुपालन करने में विफल रहा - जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हुए याचिकाएं स्वीकार की गईं की वे ईंट भट्टे को दिया गया लाइसेंस रद्द करें.

यह निर्धारित किया गया कि प्रदूषण सामग्री को निर्धारित स्तर के 1/5 या 1/6 तक कम करने का सीधा संबंध गाँव की 'आबादी' और स्कूल से ईंट भट्ठे की दूरी कम करने से है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कौवे के उड़ते समय मापी जाने वाली एक किलोमीटर की दूरी की आवश्यकता के विपरीत, वास्तविक दूरी केवल 400/460 गज होती है, यानी न्यूनतम आवश्यक दूरी का 1/5 वां हिस्सा। 750 तक एसपीएम की सामान्य अनुमेय सीमा को ईंट भट्ठे द्वारा प्राप्त करना आवश्यक था, भले ही इसे निर्धारित 'सिटिंग पैरामीटर्स' के अनुसार स्थापित किया गया हो। हालाँकि, उन मापदंडों में पर्याप्त छूट के कारण, चूँकि ईंट भट्ठे से वायु प्रदूषण इतना गंभीर होने की संभावना थी कि इससे ग्रामीणों का जीवन दयनीय हो सकता था, सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि ईंट भट्ठे अतिरिक्त साधारण उपाय अपनाएं और प्रदूषण की मात्रा को वर्तमान स्तर के 1/5वें या 1/6वें तक कम करें।

(पैरा 15)

आगे निर्धारित किया गया, कि ईंट भट्टे को गांव की आबादी/स्कूल से अपनी दूरी के संबंध में छूट प्राप्त हुई है, एसपीएम स्तर को 750 की निर्धारित सीमा के 1/5वें या 1/6वें हिस्से तक कम करने की शर्त के अधीन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनाए गए रुख के अनुसार- प्रतिवादी नंबर 5, ईंट भट्ठा ऐसा हासिल करने में विफल रहा है, और अपने मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ इसे हासिल करने

की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए यह मानने के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है कि 6वाँ प्रतिवादी अपने ज्ञापन दिनांक 20/24 जुलाई, 2001 के माध्यम से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए लाइसेंस में निहित शर्तों का पालन करने में विफल रहा है। लाइसेंस प्रकृति में सशर्त है और ईंट भट्ठा उन शर्तों का सम्मान और अनुपालन करने में विफल रहा है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट, यमुनानगर के लिए यह अनिवार्य था कि वह इसका लाइसेंस रद्द कर दे और इसे तब तक चलाने की अनुमति न दे जब तक कि यह ऐसे प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित न कर दे जो इसके एसपीएम स्तर को कम कर दें। न्यूनतम 750 की अधिकतम निर्धारित सीमा का 1/5वाँ हिस्सा।

(पैरा 16)

एस.एस. दीनारपुर, याचिकाकर्ताओं के लिए वकील।

रामेश्वर मलिक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, उत्तरदाताओं 1 से 4 के लिए।

अरुण वालिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 5 के लिए।

राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुनीश बिंदलिश, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 6 के लिए।

न्यायधीश **सूर्य कांत,**

(1) यह आदेश 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 12838 और 18137 का निपटान करेगा क्योंकि इन मामलों में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं. ये दोनों याचिकाएं जनहित में दायर की गई हैं, जिसमें कथित तौर पर हरियाणा नियंत्रण ईंट आपूर्ति आदेश, 1972 के साथ पढ़े जाने वाले पंजाब ईंट आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रतिवादी नंबर 6 को ईंट-भट्ठा स्थापित करने और चलाने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द करने/रद्द करने के लिए सर्टिओरी रिट की मांग की गई है। । संक्षिप्तता के लिए, तथ्यों को 2006 के सीडब्ल्यूपी संख्या 12838 से लिया जा रहा है।

(2) पूर्वी पंजाब ईंट आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम, 1949 (संक्षेप में अधिनियम) जनता को उचित मूल्य पर ईंटों का समान वितरण सुनिश्चित करने और ईंट-भट्ठा मालिकों को स्थिति का फायदा उठाने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। अत्यधिक कीमत वसूलना। अधिनियम की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य ने हरियाणा ईंट आपूर्ति नियंत्रण आदेश, 1972 (संक्षेप में '1972 का आदेश') अधिसूचित किया, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है जिसमें 1 जून, 1992 और 20 सितंबर, 1996 की अधिसूचनाएँ भी शामिल हैं। 1972 के आदेश के तहत निर्धारित साइट मापदंडों के अनुसार, एक ईंट-भट्ठा तब तक स्थापित

नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह निर्धारित न्यूनतम दूरी पर स्थित न हो। निषिद्ध स्थान, जिनमें से कुछ इन मामलों से प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं:-

(डी) ग्राम लिंक रोड	30 मीटर	दूरी सड़क आरक्षण के निकटतम किनारे से मापी जानी है।
(च) गांव आबादी	1 किलोमीटर	जैसे कौवा फिरनी के बाहरी किनारे के निकटतम भाग से उड़ता है वैसे दूरी मापनी है और जहां फिरनी नहीं हैं , वहाँ आबादी के बाहरी किनारे हैं, से दूरी मापी जाती है।
(छ) स्कूल/डिस्पेंसरी	1 किलोमीटर	दूरी मापी जाती है जैसे कौआ सीमा रेखा/दीवार के निकटतम भाग से उड़ता है।
(ज) अन्य शैक्षणिक संस्था की और सार्वजनिक उपयोगिता संस्थान	1 किलोमीटर	दूरी मापी जानी है जैसे ही कौआ सीमा रेखा/दीवार के निकटतम भाग से उड़ता है।
(झ) उद्यान/नर्सरी/ वन नर्सरी	1 किलोमीटर	दूरी मापी जानी है जैसे ही कौवा निकटतम सीमा से उड़ता है।

(3) 20 सितंबर, 2006 की एक बाद की अधिसूचना के माध्यम से, 1972 के आदेश को और संशोधित किया गया है और निम्नलिखित उप- खंड (i) (केवल प्रासंगिक उद्धरण) को खंड 8 में जोड़ा गया है:–

"..............यदि बीच की अवधि के दौरान नगर पालिका की सीमाएं बदल जाती हैं या क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है या कोई स्कूल या कॉलेज भट्ठा स्थल के करीब स्थित है, तो जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय लिखित में दर्ज किए गए कारणों से लाइसेंस रद्द कर सकता है। ....

................आगे बशर्ते कि यदि शहर के विकास और योजना के कारण भट्ठे का सार्वजनिक हित में बंद हो जाना आवश्यक माना जाता है, जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंसधारी को छह महीने या उस वर्ष के 30 जून तक, जो भी बाद में हो, का नोटिस देकर भट्ठा बंद करने का आदेश दे सकता है। . (जोर दिया गया)।

(4) इस प्रकार, एक ईंट-भट्ठा आवश्यक रूप से गाँव 'आबादी' के बाहरी किनारे, स्कूल, औषधालय, बगीचे या नर्सरी, से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। यह भी प्रतीत होता है कि भले ही इसकी स्थापना के समय एक ईंट-भट्ठा ने साइटिंग मापदंडों को पूरा किया हो लेकिन बीच की अवधि में क्षेत्र को 'नियंत्रित क्षेत्र' या स्कूल या कॉलेज घोषित कर दिया गया है तो निषिद्ध दूरी के भीतर खोला गया तब जिला मजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ईंट-भट्ठे का लाइसेंस रद्द कर सकता है।

(5) वर्तमान मामले में, श्री ईश्वर प्रकाश के पुत्र विजय कुमार ने 26 फरवरी, 2001 को आवेदन किया है कि 27 कनाल भूमि पर मेसर्स ईश्वर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज (प्रतिवादी संख्या 6) के नाम और शैली में एक ईंट-भट्ठा की स्थापना के लिए लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए 4 मरला गांव बसंतपुरा, उप-तहसील रादौर, जिला यमुनानगर की राजस्व संपत्ति में स्थित है। सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, रादौर ने भूमि के स्थान का सत्यापन किया और पाया कि गांव 'आबादी' और स्कूल से इसकी दूरी 1972 के आदेश के तहत निर्धारित दूरी से बहुत कम थी, उन्होंने इसे अस्वीकार करने की सिफारिश की। उक्त आवेदन को अंततः जिला मजिस्ट्रेट, यमुनानगर ने अपने आदेश दिनांक 19 मार्च, 2001 द्वारा खारिज कर दिया।

(6) निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, हरियाणा ने हालांकि, उनके दिनांक 26 अप्रैल, 2001 के ज्ञापन द्वारा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, यमुनानगर को मामले की फाइल भेजने के लिए कहा और फिर 20/24 जुलाई, 2001 को एक आदेश पारित किया, जिसमें जिला खाद्य एवं आपूर्ति सहित संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया। नियंत्रक, यमुनानगर ने कहा कि 1972 के आदेश के खंड 21 में निहित छूट की शक्ति के कथित प्रयोग में, राज्य सरकार ने प्रतिवादी संख्या 6 को ईंट-भट्ठे की दूरी की शर्त के संबंध में गाँव आबादी और स्कूल से, हालाँकि कुछ शर्तों के अधीन 'छूट' प्रदान की थी। । उपर्युक्त आदेश दिनांक 20/24 जुलाई, 2001 इस प्रकार है:—■

"2. राज्य सरकार ने हरियाणा ईंट आपूर्ति नियंत्रण आदेश, 1972 के खंड 21 के तहत अनुदान के लिए आदेश के खंड 4 के उप खंड (iii)(एफ)(जी) के संचालन से छूट प्रदान की है। मैसर्स ईश्वर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज ग्राम बसंतपुरा, जिला-यमुनानगर को ईंट भट्ठा लाइसेंस इस शर्त के अधीन है कि भट्ठा मालिक साइट पर 100 फीट से अधिक ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण कक्ष और चिमनी का निर्माण करेगा। यह इस शर्त के अधीन है कि गुरुत्वाकर्षण कक्ष की स्थापना के बाद, बीकेओ द्वारा यह

सुनिश्चित करना होगा कि प्रदूषण सामग्री वर्तमान स्तर के 1/5वें या 1/6वें स्तर तक कम हो गई है जिसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा से पता लगाया जा सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रारंभ में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा बीकेओ को अनंतिम आधार पर लाइसेंस दिया जाता है। उक्त नियंत्रण आदेश और समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत ईंट भट्ठा लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित वांछित ऊंचाई की आवश्यकता के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कक्ष और चिमनी के निर्माण के बाद ही, आप अपना मामला लाइसेंसिंग प्राधिकारी को नियमित लाइसेंस देने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह आगे निर्देशित किया जाता है कि जब तक संरचनाएं खड़ी नहीं हो जातीं और भौतिक रूप से सत्यापित नहीं हो जातीं, तब तक ईंट भट्टा मालिक द्वारा कोई भी ईंट नहीं बनाई जानी चाहिए। (जोर दिया गया)।

(7) प्रतिवादी नंबर 6 ने उपरोक्त पुनरुत्पादित शर्तों को स्वीकार कर लिया और जिला टाउनर प्लानर साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके बाद, 23 नवंबर, 2004 को छठे प्रतिवादी को अनंतिम लाइसेंस प्रदान किया गया, जिसे ईंट-भट्ठे की चिमनी और गुरुत्वाकर्षण कक्ष के निर्माण के सत्यापन के बाद 6 जून, 2005 को नियमित कर दिया गया।

(8) ईंट-भट्ठे के लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र और परिणामी स्थापना पर सवाल उठाते हुए, याचिकाकर्ताओं, जो बसंतपुरा गांव के निवासी हैं, ने आरोप लगाया कि चूंकि ईंट-भट्ठा गांव आबादी से 450 गज की दूरी पर स्थित है, सरकारी मॉडल स्कूल से 460 गज की दूरी पर, स्वर्ण सिंह और देस राज के आवासीय घरों से क्रमशः 50 और 70 गज की दूरी पर और सोहन सिंह के आम और अमरूद के बगीचे से 400 गज की दूरी पर , न केवल 1972 के आदेश में निहित साइटिंग मापदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है, 6वां प्रतिवादी प्रदूषित उत्सर्जन का एक निरंतर स्रोत बन गया है जो गांव समुदाय और आसपास की कृषि भूमि /बगीचे के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

(9) प्रस्ताव की सूचना के जवाब में, ईंट-भट्ठा सहित उत्तरदाताओं ने अपने संबंधित जवाबी हलफनामे दाखिल किए हैं।

(10) उपरोक्त देखे गए तथ्य उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 द्वारा मोटे तौर पर स्वीकार किए गए हैं। हालांकि वे मुख्य रूप से 1972 के आदेश के खंड 21 के बल पर अपनी कार्रवाई का बचाव करते हैं, इस तथ्य के साथ कि 7 जून, 2005 को कथित तौर पर गोलीबारी के बाद, प्रतिवादी-ईंट-भट्ठा ने "सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रूड़की द्वारा आयोजित निगरानी रिपोर्ट" की एक फोटो कोपी प्रस्तुत की, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि चिमनी की ऊंचाई 120 फीट थी और एसपीएम (सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर) 750 की अनुमन्य सीमा के विपरित 377 (अधिकतम) थी। ।

(11) इसके विपरीत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने प्रति-शपथपत्र के पैरा संख्या 9 और 11 में निम्नलिखित स्टैंड के साथ आए हैं:–

"9. रिट याचिका के पैरा नंबर 9 की सामग्री के जवाब में, यह कहा गया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ईंट भट्टों के लिए वायु उत्सर्जन के लिए विशिष्ट पैरामीटर तय किए गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ईंट भट्ठे से वायु उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 750 एसपीएम है और वर्तमान में उक्त ईंट भट्ठा इसके मुकाबले 750 की सीमा के विपरित 377 (अधिकतम) एसपीएम प्राप्त कर रहा है। लेकिन उक्त ईंट भट्ठा ईंट भट्ठे द्वारा स्थापित मौजूदा नियंत्रण उपायों के साथ एसपीएम के स्तर को 1/5 या 1/6 तक कम नहीं कर सकता है।"

11. रिट याचिका के पैरा संख्या 11 का पहला भाग उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 से संबंधित है और इसलिए इसका उत्तर उनके द्वारा दिया जाएगा। आगे कहा गया है कि उक्त ईंट भट्ठा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित वायु उत्सर्जन मानक को प्राप्त कर रहा है, लेकिन उक्त ईंट भट्ठा अपनी प्रदूषण सामग्री को मौजूदा नियंत्रण उपायों के साथ। 1/5 या 1/6 स्तर तक कम नहीं कर सकता है। न ही उन्होंने इसके लिए कोई योजना प्रस्तुत की है", (जोर दिया गया)

(12) दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 6 ईंट भट्ठा ने एक प्रारंभिक आपत्ति ली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रिट याचिका किसी भी जनहित का संमर्थन नहीं करती है। बल्कि यह एक तुच्छ याचिका है जो केवल दुर्भावनापूर्ण इरादों से दायर की गई है। जब याचिकाकर्ता विज्ञापन प्राप्त करने में विफल रहे 2004 के एक सिविल सूट संख्या 390 में अंतरिम निषेधाज्ञा जिसका शीर्षक जियान सिंह और अन्य बनाम खुशी राम और अन्य की स्थापना की गई जगाधरी की सिविल अदालत के समक्ष, जिसमें वादी संख्या 1 और 3 पहली रिट याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 और 4 के सगे भाई थे। उक्त सिविल मुकदमा 11 जून, 2005 को खारिज कर दिया गया था और इसके खिलाफ की गई अपील भी 24 फरवरी, 2006 को वापस ले ली गई थी। आरोप है कि वादी में से एक सुरिंदर सिंह ने मुकदमे से अपना नाम वापस ले लिया था। ईंट-भट्ठे ने ईंटें बनाने के लिए उसकी जमीन से मिट्टी खरीदने के लिए उसके साथ एक समझौता किया। आगे बताया गया है कि 2004 का सीडब्ल्यूपी नंबर 19197 गांव बसंतपुरा की ग्राम पंचायत द्वारा इसी कारण से दायर किया गया था, जिसे 17 जनवरी, 2005 को वापस ले लिया गया था। रिट याचिका को वर्तमान प्रथम रिट याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 का सगा भाई भी बताया गया है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 3 ग्राम पंचायत का सदस्य था जिसने पहले अपनी रिट याचिका वापस ले ली थी। गुण-दोष के आधार पर, किसी भी प्रदूषण को फैलाने के आरोपों का खंडन किया गया है।

(13) हम सबसे पहले ऊपर देखी गई प्रारंभिक आपत्ति से निपटने और उसे अस्वीकार करने का प्रस्ताव करते हैं। सिविल कोर्ट ने, जैसा कि उसके फैसले से पता चलता है, मुकदमे का फैसला गुण-दोष के

आधार पर नहीं किया, बल्कि यह देखने के बाद उसे खारिज कर दिया कि 1972 के आदेश के खंड 19 के तहत, आदेश के खिलाफ निदेशक के समक्ष अपील कायम रखी जा सकती थी। जिला मजिस्ट्रेट और वादी के लिए उपलब्ध उस प्रभावी उपाय को ध्यान में रखते हुए, उनके पक्ष में कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती थी। सिविल कोर्ट ने आगे कहा कि निषेधाज्ञा मुकदमा दायर करने के समय "केवल भौतिक संरचनाएं बनाई जा रही हैं, ईंट भट्ठा अभी तक चालू नहीं हुआ है। निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, हरियाणा द्वारा मानदंडों के अनुसार वांछित गुरुत्वाकर्षण कक्ष और चिमनी को उठाया जा रहा है और आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही, ईंट भट्ठा संचालन में आएगा। पहली अपील भी वापस ले ली गई थी। विद्वान वकील ने कहा कि अपीलकर्ता अपील को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। इस न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा दायर की गई रिट याचिका को इस छूट के साथ वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया कि "याचिकाकर्ता कार्रवाई के उसी कारण पर एक नई याचिका दायर कर सकते हैं"। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने ग्राम पंचायत को अपनी रिट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी, ~हालाँकि, इसमें संशोधन करने के बजाय, ग्राम पंचायत इसे वापस ले लिया। नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ समान। सटीक होने के लिए, मुद्दा यह है कि क्या साइटिंग मापदंडों में ढील दी जा सकती है और यदि हां, तो क्या प्रतिवादी नंबर 6-ईंट-भट्ठा साइटिंग मापदंडों में ढील देते समय राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है, सिविल न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया। वास्तव में, सिविल कोर्ट ने ठीक ही कहा कि ईंट-भट्ठे द्वारा उत्सर्जन के निर्वहन के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई गई शर्तों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दा केवल तभी उठ सकता है जब ईंट भट्ठा कार्यात्मक हो जाए (इसके बाद) 7 जून, 2005 को निकाल दिया गया)।

(14) मामले की खूबियों पर आते हुए, हमारा विचार है कि यह प्रश्न कि क्या 1972 के आदेश के खंड 21 के कथित अभ्यास में राज्य सरकार द्वारा साइटिंग मापदंडों में ढील दी जा सकती है या नहीं और यदि तो किस हद तक, यह विचार का प्रश्न ही नहीं उठता। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि छूट देते समय, राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी नंबर 6-ईंट भट्ठा को इस शर्त के अधीन कर दिया कि "गुरुत्वाकर्षण कक्ष की स्थापना के बाद, बीकेओ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदूषण की मात्रा कम हो।" इसे घटाकर 1/5 या 1/6 कर दिया गया है, जिसका पता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा से लगाया जा सकता है।

(15) प्रदूषण की मात्रा को निर्धारित स्तर के 1/5 या 1/6 तक कम करने की शर्त का गांव 'आबादी' और विद्यालय से ईंट भट्ठे की दूरी कम करने के साथ स्पष्ट सीधा संबंध है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कौवे के उड़ते समय मापी जाने वाली एक किलोमीटर की दूरी की आवश्यकता के विपरीत, वास्तविक दूरी केवल 400/460 गज है, यानी, न्यूनतम आवश्यक दूरी का 1/5 वां हिस्सा। एसपीएम की सामान्य अनुमेय सीमा 750 तक ईंट-भट्ठे द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक थी, भले ही इसे निर्धारित 'साइटिंग

पैरामीटर्स' के अनुसार स्थापित किया गया हो। हालाँकि, उन मापदंडों में पर्याप्त छूट के कारण, चूंकि ईंट-भट्ठे से इतनी गंभीरता का वायु प्रदूषण होने की संभावना थी कि इससे ग्रामीणों का जीवन दयनीय हो सकता था, सक्षम प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि ईंट-भट्ठा असाधारण उपाय अपनाने चाहिए और प्रदूषण सामग्री को वर्तमान स्तर के 1/5 या 1/6 तक कम करना चाहिए।

(16) छठे प्रतिवादी - ईंट भट्ठा ने उपरोक्त बताई गई शर्त को बिना शर्त और बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। इसने अन्य वैधानिक प्राधिकारियों से उक्त शर्त का पालन करने के वचन के साथ एनओसी प्राप्त कर लई। हालाँकि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी है, वह हमारे द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि "ईंट भट्ठा मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपायों से एसपीएम के स्तर को 1/5 या 1/6 तक कम नहीं कर सकता है और न ही उसने इसके लिए कोई योजना प्रस्तुत की है"। हम यहां स्पष्ट कर सकते हैं कि एसपीएम जो वर्तमान में ईंट भट्ठे द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, उसे प्राप्त करना आवश्यक होता या उसके द्वारा बनाए रखा जाता यदि यह गांव आबादी या स्कूल से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता। ईंट भट्टे को गांव की आबादी/स्कूल से उसकी दूरी के संबंध में छूट प्राप्त हुई, बशर्ते कि एसपीएम स्तर को 750 की निर्धारित सीमा से 1/5वां या एल/6वां कम किया जाए और उसके अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा लिया गया रुख, ईंट-भट्ठा ऐसा हासिल करने में विफल रहा है, और अपने मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ इसे हासिल करने की स्थिति में भी नहीं है, हो सकता है कोई अन्य निष्कर्ष नहीं बल्कि यह मानना चाहिए कि छठा प्रतिवादी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए लाइसेंस में निहित शर्तों का पालन करने में विफल रहा है, - अपने ज्ञापन दिनांक 20/24 जुलाई, 2001 के माध्यम से। लाइसेंस प्रकृति में सशर्त होने और ईंट भट्ठा उन शर्तों का सम्मान करने और उनका अनुपालन करने में विफल रहा है, जिला मजिस्ट्रेट, यमुनानगर के लिए यह अनिवार्य था कि वह उसका लाइसेंस रद्द कर दे और उसे तब तक चलाने की अनुमति न दे जब तक यह ऐसे प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित करता है जो इसके एसपीएम स्तर को कम से कम 750 की अधिकतम निर्धारित ~सीमा के 1/5वें हिस्से तक कम कर देगा।

(17) उपर्युक्त कारणों से, हम इन रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हैं और जिला मजिस्ट्रेट, यमुनानगर को निर्देश देते है कि प्रतिवादी नंबर 6-ईंट भट्ठा को दिया गया लाइसेंस कानून के अनुसार तुरंत रद्द कर दिया जाए और उसके बाद इसे तब तक चलने की अनुमति न दी जाए जब तक कि यह राज्य द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन नहीं करता हो। सरकार ने अपने आदेश दिनांक 20/24 जुलाई, 2001 के तहत साइटिंग मापदंडों में छूट दी है।

(18) इस न्यायालय को एक अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा